लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1-15 अगस्त 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक-23

"आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, विफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है।

: स्वामी विवेकानंद

अनाज आपूर्ति के लिए 'ग्रेन एटीएम'

➡ P2

जश्न बनाम त्रासदी

➡ P3

किसान जैविक खेती अपनाएं, आमदनी बढ़ाएं

➡ P5

'सक्षम हरियाणा' के सकारात्मक परिणाम

➡ P6

ग्राम दर्शन पोर्टल पर दे सकेंगे सुझाव व शिकायत

➡ P7

चौगरदे तै बाग हर्‌या, घनघोर घटा सामण की

➡ P8

त्वरित मिलेगी पुलिस मदद

विशेष प्रतिनिधि

हरियाणा में आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए नागरिकों को 112 नंबर डायल करना होगा। यह नई हेल्पलाइन 100 (पुलिस), 101 (फायर) और 108 (एम्बुलेंस) जैसी सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए चौबीसों घंटे काम करेगी।

इस प्रणाली का संचालन लगभग 5,000 प्रशिक्षित कर्मियों, स्पॉट पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा-बॉक्स, स्ट्रेचर, अपराध निवारण किट आदि सहित 23 इन-फ्लीट आइटम से लैस 630 नए चार पहिया वाहनों और परियोजना सलाहकारों द्वारा किया जाएगा जिसमें सी-डैक टोटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करेगा।

पंचकूला में 42 करोड़ रुपए की लागत से बने हरियाणा इमरजेंसी रिस्पोंस सेंटर में डायल 112 कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया। सभी जिलों के लिए 630 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। ये सभी गाड़ियां डायल 112 योजना के तहत त्वरित सहायता उपलब्ध करवाएंगी।

कम्युनिकेशन अधिकारी शिकायतकर्ता की पूरी बात को सुनकर और लोकेशन की वास्तविक स्थिति की जानकारी निर्धारित फोर्मेट में अपलोड करेगा। इसके बाद यह शिकायत तत्काल डिस्पेच विभाग को फारवर्ड हो जाएगी। इसके बाद आगे की कार्यवाई शुरू हो जाएगी। इस विंग में जानकारी लेने के दौरान मुख्यमंत्री ने 112 नंबर पर डायल करके कम्युनिकेशन अधिकारी से बात भी की। एसपी नीतिश अग्रवाल ने बताया कि इस विंग को तीन भागों में बांटा गया है जिनमें स्वास्थ्य, फायर और पुलिस सेवा शामिल है।

डायल 112 के तहत शिकायतों पर कार्रवाई के लिए जिला या थाने की सीमा की बंदिश नहीं होगी। कंट्रोल रूम से शिकायतकर्ता की लोकेशन के निकटतम वाहन स्टाफ को सूचना जाएगी जो कि तत्काल पहुंचकर शिकायतकर्ता को मदद उपलब्ध करवाएगें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसी उद्देश्य से डायल 112 शुरू किया गया है। इस अत्याधुनिक प्रणाली से समग्र सुरक्षा परिदृश्य में और सुधार होगा और राज्य भर में अपराध की रोकथाम में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन साल पहले उन्होंने इज़रायल के जेरूसलम का दौरा करने के दौरान एक त्वरित आपातकालीन प्रणाली देखी थी, जिसमें केवल 90 सेकंड के समय में हर जरूरतमंद को मदद सुनिश्चित की जा रही थी। वहां 5,000 से ज्यादा लोग एंबुबाइक सर्विस से जुड़े हैं। ये सभी 247 आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे ही उनके मोबाइल में अलार्म बजता है, वे घायलों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत अपनी एंबुबाइक के साथ दुर्घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। प्राथमिक उपचार देने से लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने तक ये वॉलंटियर्स हर घायल व्यक्ति की मदद के लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं।

जवाबदेही सुनिश्चित होगीः गृह मंत्री

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा 112 परियोजना कामकाज में पारदर्शिता लाएगी और विभिन्न आपातकालीन सेवा मुहैया करवाने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी जिससे हरियाणा के निवासियों को त्वरित आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

स्वामित्व योजना के तहत आवंटित होंगी प्रॉपर्टी डीड

प्रदेश में 15 सितंबर तक स्वामित्व योजना को लागू कर दिया जाएगा। राज्य में ड्रोन फ्लाइंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब स्वामित्व योजना में नक्शे बनाने का काम जारी है। सभी जिला उपायुक्तों को इस मामले में निर्देश दिए हुए हैं कि आगामी 15 सितंबर तक अपने-अपने जिलों में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए।

योजना के तहत प्रदेश में प्रॉपर्टी डीड बन रही है जिनको बाद में आवंटित किया जाएगा। राज्य में 6,350 गांव लाल डोरे वाले हैं जिनमें आबादी है। उनमें से 1,511 गांवों की प्रॉपर्टी डीड बन चुकी है और 72 हजार 445 प्रॉपर्टी डीड आवंटित हो चुकी हैं।

लाल डोरे में जो मकान बने हैं उनके मालिकों को सरकार मलकियत देने जा रही है। इससे मकान मालिक खरीद-फरोख़्त कर सकेंगे व बैंक से लोन भी ले सकेंगे। स्वामित्व योजना में गांव के साथ-साथ शहर का कार्य भी पूरा करने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि शहरों के विस्तार में गांव का रकबा शामिल होने से उनमें भी लालडोरा आ चुका है।

जानकारी के मुताबिक स्वामित्व योजना को लेकर हरियाणा की विधानसभा में एक संशोधित कानून भी पारित कराना होगा। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग और पंचायत विभाग की ओर से दो अलग-अलग संशोधित कानून लेकर आने होंगे।

कार्य को अंजाम देने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट जल्द देगी। इस कमेटी में राजस्व विभाग के डायरेक्टर ,स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर जनरल और पंचायत विभाग के डायरेक्टर जनरल समेत 4 जिलों के उपायुक्त शामिल हैं। ड्राफ्ट बनने के बाद उसको कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी।

हरियाणा सरकार ई-भूमि पोर्टल के जरिए विकल्प देती है जिसके बाद भू-मालिक अपनी स्वेच्छा से जमीन दे सकते हैं। जमीन मालिक खुद ही अपना रेट बताते हैं कि वह अपनी जमीन इस रेट में देना चाहते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया है और एक हाई लेवल कमेटी जो जमीन के लेनदेन को तय करती है।

वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा में कहीं से भी रजिस्ट्री हो सके इस प्रावधान को लेकर तैयारी की जा रही है। स्वामित्व योजना में गांव के साथ-साथ शहर का कार्य भी पूरा होगा।

-संवाद ब्यूरो

संपादकीय

शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत

अब हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए एक स्वर्णिम कल की इबारत लिखने जा रहा है। प्रदेश की नई शिक्षा नीति की प्राथमिकताओं में महिला-शिक्षा, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिन 15 सरकारी कॉलेजों की आधार शिक्षा रख दी गई है उनमें 11 कॉलेज केवल छात्राओं के हैं। यही नहीं आईआईटी में शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को 500 रुपए मासिक के छात्रवृति भी लागू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री का यह भी संकल्प है कि जहां एक ओर शिक्षा को जीवनमूल्यों से जोड़ा जा रहा है वहीं दूसरी ओर रोज़गार की संभावनाओं से भी पूरी तरह जोड़ा जाए।

गत कुछ माह की अवधि में हरियाणा में सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है और अब नए-नए 'ऐप' व 'प्लेटफार्म' के माध्यम से प्रशासन एवं राज्य सरकार हर क्षेत्र में जन-जन के साथ सीधे संपर्क में है। अब सब कुछ पारदर्शी भी है, सरल भी और अबाध भी। बात सिर्फ सरकारी योजनाओं की खिड़कियां खोलने की नहीं है। अब प्रदेश का किसान व आम आदमी अनेक खिड़कियों का स्वामी भी है। उसे 'माउस' की एक क्लिक या अपने मोबाइल फोन पर भी 'अपनी फ़सल, अपना ब्यौरा', 'मेरा पानी मेरी विरासत' और कहां, क्या व कब करना उचित होगा, आदि की जानकारी उपलब्ध है।

शिक्षा क्षेत्र में 'स्वर्णिम कल'

हरियाणा का शिक्षा विभाग अब युवाओं के लिए एक 'स्वर्णिम कल' की परिकल्पना के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शिक्षा के समग्र विकास के लिए कुछ नई क्रांतिकारी योजनाएं तैयार की हैं।

वर्ष 2020 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसविदा तैयार किया था, जिसमें देश के शिक्षा तंत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने का संकल्प निहित था। हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी प्रदेश के युवाओं के लिए स्वर्णिम भविष्य की नई योजनाओं को मूर्त रूप देने का संकल्प लिया है।

भावी- शिक्षा नीति के विषय में स्वयं मुख्यमंत्री ने अपनी अवधारणा स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमारी सरकार के लिए शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमें कुछ ऐसी दूरदर्शी निर्णय लेने होंगे, जिनसे प्रदेश के युवाओं को विकास के मार्ग पर दक्ष किया जा सके और 'कारपोरेट सैक्टर' में भी उनके लिए नई संभावनाएं पैदा हो सकें। प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थानों का भी प्रयास है कि छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा व आदर्श जीवन मूल्यों पर आधारित विकास का मार्ग दर्शाया जा सके।

युवाओं को स्कूली स्तर पर ही एक सुदृढ नींव प्रदान करने के लिए 113 नए 'संस्कृति मॉडल स्कूल' खोले गए हैं, ताकि जीवन मूल्यों व मानवीय सिद्धांतो पर केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। अब प्रदेश में 'संस्कृति मॉडल स्कूलों' की कुल संख्या 136 हो गई है। यही नहीं, इनमें अब 9वीं से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क पुस्तकें भी वितरित की जा रही हैं और 'हरियाणा शिक्षक परीक्षा योग्यता' को भी अब आजीवन स्वरूप दिया जा रहा है।

सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि प्रदेश में पहली बार 'सुपर-100' योजनाओं पर काम शुरू हो, जिनका उद्देश्य छात्रों को 'जेईई', 'आईआईटी', 'एनईईटी' सरीखी प्रतियोगिताओं के लिए नि» शुल्क शिक्षा और निःशुल्क आवास-सुविधा प्रदान करना होगा।

- डा चंद्र त्रिखा

अनाज आपूर्ति के लिए ग्रेन एटीएम

सरकारी राशन डिपुओं के आगे अब अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को न तो लंबी लाईनों में लगना होगा और न ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका मिलेगा। हरियाणा सरकार अब प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए 'ग्रेन एटीएम' (अनाज का एटीएम) स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है।

गुरुग्राम जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला 'ग्रेन एटीएम' स्थापित कर दिया गया है।

ये मशीनें न केवल सरकारी डिपो सचालकों को अनाज वितरण में सहायक साबित होंगी बल्कि इससे डिपो संचालकों का समय भी बचेगा। फरूखनगर में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इन अन्न-आपूर्ति मशीनों को प्रदेशभर में सरकारी डिपुओं पर लगाने की योजना है।

यह एक स्वचालित मशीन है जो कि बैंक एटीएम की तर्ज पर कार्य करती है। 'यूनाइटेड नेशन के:वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' के तहत स्थापित की जानी वाली इस मशीन को ऑटोमेटिड, मल्टी कमोडिटी, ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा गया है।

कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी अंकित सूद का कहना है कि अनाज के मापतोल को लेकर इसमें त्रुटि न के बराबर है और एक बार में यह मशीन 70 किलोग्राम तक अनाज पांच से सात मिनट में निकाल सकती है।

मशीन में लगी टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक मशीन भी लगी हुई है, जहां पर लाभार्थी को आधार या राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। बायोमेट्रिक से प्रमाणिकता होने पर लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित अनाज स्वतः मशीन के नीचे लगाए गए बैग में भर जाएगा। इस मशीन के माध्यम से तीन तरह के अनाज गेहूं, चावल और बाजरा का वितरण किया जा सकता है। फिलहाल फर्रुखनगर में स्थापित ग्रेन एटीएम मशीन से गेहूं का वितरण शुरू कर दिया गया है।

वितरण प्रणाली में और पारदर्शिता आएगीः चौटाला

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि 'ग्रेन एटीएम' लगने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा माप न मिलने को लेकर तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा बल्कि सरकारी डिपुओं पर अनाज घटने का झंझट भी खत्म होगा और सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी।

रोजगार के लिए तीन लाख तक का ऋण

हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु 3 लाख रुपए तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है।

जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक तथा आयु 18 से 55 वर्ष है, इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी, वह दी जाएगी।

बूटिक, सिलाई-कढ़ाई, ऑटो, ई-रिक्शा, मसाला/अचार, इकाईयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट गारमेंटस, कम्प्यूटर जांच वर्क्स इत्यादि या जिन कार्यों को महिलाएं करने में सक्षम हों, उन सभी कार्यों के लिये ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जायेगी ताकि महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्यकुशलता की कमी महसूस न हो।

सलाहकार संपादक :	डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक :	मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम :	संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक, मनोज चौहान
संपादन सहायक :	सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन :	गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट :	विकास डांगी

गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ़्त अन्न

कोरोना काल में हरियाणा सरकार गरीबों की हमदर्द बनकर उभरी है। लॉकडाउन के कारण प्रदेश के लाखों गरीब परिवार न तो दिहाड़ी पर जा पाए और न ही छोटी-मोटी नौकरी पर। ऐसे में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के माध्यम से उनके घर-द्वार तक लगातार पांच किलो गेहूं प्रति सदस्य पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य में करीब 27 लाख परिवारों को यह अनाज मुफ़्त दिया जा रहा है। अगर चालू माह जुलाई की बात करें तो इस माह में प्रदेश के 27,04,846 राशन कार्ड धारकों को करीब 60,391 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया जा रहा है।

गरीबों को मिली राहत

कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष 26 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे कि सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को खाने की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरीब हितैषी सोच के मद्देनजर अप्रैल 2020 से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' शुरू की गई। इसमें एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य मुफ़्त उपलब्ध कराया गया। यह अनाज पूर्व में चल रही 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त वितरित किया गया। कोरोना से कुछ हालात सुधरने पर उद्योग-धंधे चलने के कारण उक्त योजना नवंबर 2020 तक चलाई गई। कोरोना सकंट के बीच सरकार ने इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है।

मुफ्त राशन नवंबर 2021 तक

इस साल फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' मई 2021 से पुनः आरंभ कर दी गई ताकि गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, इस योजना की समयावधि को दिवाली तक बढ़ा दिया गया है, यानि मुफ़्त राशन नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड) बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आटा, बाजरा, चीनी, नमक, सरसों तेल उनकी पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत उपरोक्त श्रेणी के कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य प्रति माह जो मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है उससे गरीब तबके के लोगों को बहुत राहत मिली है।

- संवाद ब्यूरो

हरियाणा सरकार ने भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार' के लिए 9 अगस्त तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं।

राज्य सरकार द्वारा टीबी पीड़ितों को निःशुल्क जांच, इलाज व दवाएं उपलब्ध करवाने के अलावा भत्ते के रूप में 500 रुपए प्रति माह दिये जाते हैं। रजिस्टर्ड करवाने वाले को भी 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है

भारत पाक विभाजन पर विशेष लेख

जश्न बनाम त्रासदी

डा. चंद्र त्रिखा

यह एशिया के उस भूखण्ड की गाथा है जिसने विदेशी दास्तां से मुक्ति के लम्हों में जश्नों व त्रास्दियों को एक साथ जिया, भोगा और अपने नवनिर्माण की यात्रा उमंगों व मर्मान्तक पीड़ाओं के परिवेश में शुरू की। इसी भूखण्ड में करोड़ों आबाद लोगों ने नए आशियानों के लिए अपने भरे पूरे घर छोड़े। यह प्रक्रिया अब भी इतिहास में सबसे बड़े 'आबादी माइग्रेशन' के रूप में बयान होती है। 14 अगस्त, 1947 से पूर्व जो भूखण्ड एक भरा पूरा देश था, अब उसका भूगोल बिल्कुल बदल चुका है। अब वह भूखण्ड तीन स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों में विभाजित है।

जब अतीत एक हो, विरासत सांझी हो, सांस्कृतिक जिंदगी एक जैसी हो, आर्थिक विषमताओं का स्तर एक जैसा हो, जंगल, नदियां, वनस्पति, मिट्टी की गंध, मुहावरे, दुआएं, प्रार्थनाएं और गालियां कमोबेश एक जैसी हों तो अलगाव का अलाव जलाना आसान नहीं होता। मगर अलग अलख जले। और अब उन्हीं अलावों की रौशनी में ज़िन्दगी जीने का करीना तय हो चुका है।

तीनों में, आकार व आबादी की दृष्टि से 32 लाख 87 हज़ार 263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मुख्य राष्ट्र हमारा भारत है। यद्यपि इसके 78,114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है। उसमें से 8,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को दे दिया है। चीन के कब्जे में वैसे भी 37,555 वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश भी है और इन तीनों विभाजित भूखण्डों में भी सबसे बड़ा है। 14 अगस्त, 1947 को भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आने वाला देश पाकिस्तान इस समय 7,96,095 वर्ग किलोमीटर में फैला है।

1971 से पूर्व यह देश इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान था। मगर बांग्लादेश के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद यह देश सिकुड़कर छोटा हो गया। अपनी ढेरों विसंगतियों एवं अस्थिर राजनैतिक तंत्र के बावजूद पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने अस्तित्व के लिए निरंतर जूझ रहा है।

तीसरा खण्ड 1971 में अस्तित्व में आया। बांग्लादेश के रूप में यह स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में विश्व के मानचित्र पर उभरा। इसका क्षेत्रफल 1,48,393 वर्ग किलोमीटर है। यह भूखण्ड 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का एक अंग था और तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था।

वैसे कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति सहज रूप में नहीं करता, मगर इस भूखण्ड में एक से तीन राष्ट्रों में विभाजित भारत, पाक व बांग्लादेश को अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आने से पूर्व कुछ ज़्यादा ही त्रास्दियों के रक्तरंजित रास्तों से गुजरना पड़ा।

भारत-पाक विभाजन को अब भी विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या-माइग्रेशन माना जाता है। समान विरासत, सांझी संस्कृति, कमोबेश एक जैसा मुकद्दर व लगभग एक जैसे पहरावे व जीवनशैली वाले लोग आज लगभग 65 वर्ष बाद भी पीड़ा के परिवेश से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। शरणार्थी, रिफ्यूजी, मुहाजिर, बांग्लादेशी आदि शब्द एक अभिशाप की तरह अभी भी करोड़ों लोगों पर चस्पां हैं। नफ़रत, मोहब्बत, मिलकर जीने और एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने आदि मिले-जुले जज़्बों के साथ इस भूखण्ड के तीनों राष्ट्रों ने अपने समकालीन इतिहास की अब तक की इबारत लिखी है।

आतंकवाद, गरीबी, धार्मिक असहिष्णुता व प्राकृतिक आपदाओं से अब तक मुक्त नहीं हो पाए तीनों देश। आज भी तीनों पड़ौसियों का एक-दूसरे के घर में आना-जाना कड़ी जांच-पड़ताल के बिना मुमकिन नहीं है। तीनों पड़ौसियों में से बीच वाला भूखण्ड भारत है। उस पर दोहरी जिम्मेदारी भी है, दोहरी मार भी है। आज इतने वर्षों के तनाव के बावजूद भी हम लोग गालिब, इकबाल, टैगोर, फ़ैज़, काज़ी नज़रुल इस्लाम, यशपाल, कृष्ण चन्दर, मंटो, अमृता प्रीतम आदि को अपनी अदबी ज़िन्दगी से अलग करके नहीं देख पाए। नदियों के नाम वही हैं। वही सतलुज, वही रावी, ब्यास, जेहलम और चनाब। वही सिंध व सिंधु घाटी की सभ्यता, वही भर्तृहरि, गुरु गोरखनाथ, बाबा फ़रीद, वही बाबा गुरु नानक, बुल्लेशाह, ख्वाजा गरीब नवाज़, वारिस शाह। हम इन सबकी सांझेदारी से मुक्त तो नहीं हो पाए। इन्हें बांटना भी नामुमकिन रहा।

कभी-कभी लगता है कि 14-15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के साथ उसी शाम पूरे उपमहाद्वीप में पश्चाताप-दिवस भी मनाया जाना चाहिए ताकि उन करोड़ों परिवारों की नियति को याद किया जाए और इतिहास की आत्मा से भविष्य के लिए सद्बुद्धि की दुआएं की जाएं। अनेक राजनैतिक विश्लेषक एवं इतिहासकार मानते हैं कि यदि उस समय के राजनैतिक नेतृत्व ने अपने चिंतन का दायरा सत्ता के गलियारे से बाहर तक फैलाया होता तो विभाजन की त्रासदी टल सकती थी।

आरटीआई के बाद अब आरटीएस

एक दौर था जब सरकारी तंत्र में गोपनीयता के नाम पर आम आदमी को हर उस जानकारी या सूचना से वंचित रखा जाता था जो किसी भी तरह से उसके काम की हो सकती थी। लेकिन 'आरटीआई' यानी सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से सरकारी महकमों की कार्य-शैली में एक 'ांतिकारी बदलाव देखा व महसूस किया गया। इसे इस अधिनियम का जादुई करिश्मा ही कहा जा सकता है कि आरटीआई आज हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ा हुआ है। सूचना तक जनसाधारण की पहुंच हो जाने के बाद अब जरूरत है, 'आरटीएस' यानी सेवा का अधिकार को सख्ती से लागू करने की और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शुरू से ही सुशासन पर जोर रहा है। इसी कड़ी में, जनसाधारण को सरकारी महकमों द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी समय पर सुनिश्चित करवाने के मकसद से राज्य सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम को सही ढंग से लागू करवाने के लिए बाकायदा हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग बनाया गया है। आयोग के चीफ कमीश्नर के प्रयासों से आज राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की 551 सेवाएं व योजनाएं इस कानून के दायरे में हैं।

आयोग की सचिव मीनाक्षी राज का कहना है कि आयोग का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी विभागों द्वारा इस अधिनियम को सही ढंग से लागू किया जाए। इस उद्देश्य के लिए आयोग, अधिनियम के अनुरूप सेवा डिलीवरी में विफल रहने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है और ऐसे मामलों को निर्णय के लिए प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी या द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी को भेज सकता है। सेवा डिलीवरी से जुड़े कार्यालयों तथा प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी या द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के दफ्तरों का निरीक्षण कर सकता है। इस अधिनियम के तहत कार्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

अधिनियम की धारा-3 के तहत अतिरिक्त सेवाएं अधिसूचित करने तथा पहले से जारी अधिसूचनाओं में संशोधन की सिफारिश भी कर सकता है। सेवा का अधिकार आयोग के पास ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल पदनामित अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने और कोताही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी से पात्र व्यक्ति को 5 हजार रुपए तक मुआवज़ा दिलवाने का भी अधिकार है।

सात दिन में निदान आवश्यक

यदि आवेदनकर्ता के आवेदन में कोई कमी रह गई हो तो इसकी जानकारी उसे तुरंत दी जानी चाहिए। अगर निर्धारित समयावधि में वह सेवा व्यक्ति को नहीं मिलती तो 30 दिन के अंदर फर्स्ट रिड्रेसल अथॉरिटी को इसकी शिकायत की जा सकती है। फर्स्ट रिड्रेसल अथॉरिटी से कार्य का निष्पादन नहीं होता तो वह व्यक्ति 60 दिन के अंदर सैकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी को अपनी शिकायत दे सकता है। आवेदनकर्ता की शिकायत जायज पाए जाने पर अथॉरिटी द्वारा नामित अधिकारी को 7 दिन में समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए जाएंगे।

अनियमितता मिलने पर जुर्माना

कार्य में अनियमितता पाए जाने पर ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी द्वारा नामित अधिकारी पर 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अधिकारी की गलती पाए जाने पर अथॉरिटी द्वारा आवेदनकर्ता को एक हजार रुपए का मुआवजा दिलवाने के आदेश दिए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा, एक्ट में दोनों ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी द्वारा संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है। यदि फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह 'राइट टू सर्विस कमीशन' को अपनी शिकायत दे सकता है।

-संवाद ब्यूरो

सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति में भी नियमानुसार 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों के बच्चों को हरियाणा सरकार पांच प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान करने का लाभ दे रही है।

केंद्र सरकार की तर्ज़ पर हरियाणा के कर्मचारियों और पैंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी।

सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान दें अधिकारी

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने 'माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डिवलेपमैंट अथोरिटी' द्वारा संचालित की जा रही करीब 1200 करोड़ रूपए की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने 'माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डिवलेपमैंट अथोरिटी' की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने राज्य में अधिक से अधिक क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने पर जोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में सूक्ष्म सिंचाई के तहत आने वाले क्षेत्र को पानी के स्रोत (यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नहर, तालाब या ट्यूबवेल से सींचा जाता है) के अनुसार भी पहचान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उक्त जल स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचित किए जाने के लिए भविष्य हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

उन्होंने सिंचाई विभाग को 'लिफ्ट नहर सिंचाई प्रणाली' के माध्यम से सिंचित क्षेत्र की पहचान करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत लाने के लिए प्रयास किए जाएं ताकि बचाए गए पानी का उपयोग वर्षा-सिंचित क्षेत्रों की सिंचाई के लिए किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव-वाइज भू-जल स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा तथा 30 मीटर से अधिक गहरे भू-जल स्तर वाले गांवों में किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मांगोन्मुख सिंचाई जल की आपूर्ति हेतु ब्लॉक-वाइज सतही जल की उपलब्धता एवं मासिक-मांग की गणना की जाएगी।

प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़ी

हरियाणा में श्वेत 'ाति के चलते पिछले दो दशकों में दूध उत्पादन में ढाई गुना वृद्धि हुई है। यही नहीं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो 2016-17 में 930 ग्राम प्रति व्यक्ति थी वह आज बढ़कर 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है।

दूध उत्पादन में वृद्वि के पीछे प्रदेश सरकार की नस्ल सुधार योजना का बड़ा योगदान है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से दूध उत्पादन में प्रदेश लगातार समृद्ध हो रहा है।

कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा गाय व भैसों में नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतू चलाई गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत उत्तम नस्ल के सांडों का वीर्य लेकर गाय व भैंसों को कृत्रिम विधि से गर्भित किया जाता है जिसके कारण नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादन को बढावा मिला है।

पशुपालक इस तकनीक में काफी रुचि ले रहे हैं, यही कारण है कि गायों में लगभग 100 प्रतिशत और भैंसों में 50 से 60 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है।

मूंग की खेती रास आ गई

सेवानिवृति के बाद जीवन का सफर पूरा नहीं हो जाता, बल्कि एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसमें मन मुताबिक कुछ नया करने का अवसर मिलता है। जिससे जीवन में रोमांच व आनंद की अनुभूति होती है। वायुसेना में साढ़े 39 साल तक सेवाएं देने के बाद रेवाड़ी जाटूसाना खंड के रामपुरी गांव के ब्रहम प्रकाश ने खेती की ओर अपना रूख किया है। उन्होंने मूंग की खे ती शु रू की है।

गांव के लोगों ने ऐसा न करने की सलाह दी मगर वे नहीं माने। कहा गया कि इस ज़मीन पर मूंग की पैदावार नहीं होगी, नील गाय खेती को बर्बाद कर देंगी। उन्होंने अनुभव के तौर पर दो एकड़ ज़मीन पर मूंग की खेती की जिससे सात क्विंटल मूंग की पैदावार हुई।

उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, बावल के प्रधान वैज्ञानिक एवं वरिष्ठ संयोजक डॉ.जोगिंद्र यादव की परामर्श पर मूंग की खेती करनी शुरू की। हिसार की मंडी में उन्होनें मूंग 80 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा। ब्रहमप्रकाश किसानों के व्हाइटअप ग्रुप से भी जुड़े हैं, जिसके माध्यम से उन्हें खेती से संबंधित नई-नई तकनीक व जानकारी मिलती रहती है। इस समूह के माध्यम से भी मूंग की बिक्री करने में मदद मिल रही है। कृषि विषय पर आयोजित वेबिनार में भी भाग लेते हैं और अच्छी बातों को अपनी खेती में अपनाते हैं।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी दलाल के मुताबिक फसलों की सुगम खरीद, मुआवज़ा व अन्य योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए सरकार ने 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल शुरू किया है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे मूंग की बिजाई करें। मूंग के बीज पर प्रदेश सरकार 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा अगर जिस किसान ने पिछली बार बाजरे की बिजाई की थी वहां पर इस बार मूंग की खेती करता है तो उसे प्रति एकड़ 4 हजार रुपए दिए जाएंगे।

-संगीता शर्मा

मोरनी हिल्स में हल्दी व अदरक की खेती

मोरनी हिल्स से करीब पांच किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में बसे गांव कोल्यों में किसान रत्तन सिंह सात एकड़ के जमीदार हैं, आधुनिक खेती कर अच्छी आमदनी वाली फसलों ले रहे हैं। किसान हल्दी व अदरक की खेती करके अपनी जीविका चलाते हैं। उन्होंने बागवानी विभाग से अदरक की ट्रेनिंग ली हुई है।

खेती में घाटा हो जाए तो टमाटर, धान व मक्का की खेती भी कर फसलों से घाटा पूरा कर लेते हैं। वे सालाना एक एकड़ में 15-20 क्विंटल के करीब हल्दी का उत्पादन कर लेते हैं व बाजार में 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक जाती है। यही स्थिति अदरक में है। जुलाई में हल्दी की बिजाई करते हैं। आठ महीने में यह फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है।

बावड़ी के पानी से वे हल्दी व अदरक की सिंचाई करते हैं। जमीन दोमट है जिसमें पानी कम ठहरता है। अनेक किसान सीडीनुमा खेतों करके पैदावार अच्छी लेते हैं। उनका मानना है कि यहां गर्मी के मौसम न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी। इस कारण फसल की पैदावार ज्यादा होती है।

किसान रतन सिंह कहते हैं कि साधन संपन्न किसानों के पास पानी को स्टोर करने के बड़े -बड़े टैंक हैं। वे खेती में किसी भी प्रकार का केमिकल या दवाई का इस्तेमाल नहीं करते। पहाड़ों के मध्य में खेती करना मुश्किल जरूर है लेकिन कम लागत में फसलों की पैदावार अच्छी मिल जाती है। रतन सिंह कहते हैं कि यहां पनचक्की काफी सहायक है। पनचक्की से वे आटे की पिसाई करते हैं। रत्न सिंह ने बताया की सरकार ने खेती के लिए किसानों को 75% सब्सिडी पर पावर ट्रिलर दिये हैं। पिछले दो वर्ष से किसान पावर ट्रिलर की मदद से हल्दी, टमाटर, अदरक व अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं।

-संवाद ब्यूरो

राज्य के आठ जिलों में सैनिकों के कल्याण के लिए 'एकीकृत सैनिक सदन' बनाए जाएंगे। इनके निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।

'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना में इस वर्ष दो लाख एकड़ भूमि पर फसल विविधिकरण का लक्ष्य रखा गया था जो अब तक लगभग 90 हजार एकड़ तक पहुंच गया है।

पराली के निष्पादन के लिए कराएं पंजीकरण

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने प्रदेश के किसान भाईयों से अपील की है कि वे फसल अवशेष प्रबंधन अपनाएं ताकि पराली जलाने की नौबत ही न आये और आर्थिक लाभ भी हो। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष (2021-22) भी जो किसान स्ट्रॉ बेलर द्वारा पराली की गांठ / बेल बनाकर या बनवाकर उसका निष्पादन किसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम व अन्य औद्योगिक इकाईयों में करेगा उसे 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि 50 क्विंटल एवं 20 क्विंटल प्रति एकड़ पराली उत्पादन को मानते हुए दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 230 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

किसान भाईयों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर अपना पंजीकरण करवाएं। किसान पोर्टल पर 'पि रेसिडु मैनेजमेंट लिंक पर जाकर पराली की गांठ/बेल के उचित निष्पादन के लिए 'पंजीकरण' शीर्षक पर क्लिक करके पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि अधिकारी या टोल फ्री नम्बर 1800 180 2117 पर सम्पर्क कर सकते हैं। यह पोर्टल किसानों और उद्योगों को पराली की मांग और आपूर्ति के लिए मंच प्रदान करता है। इस पोर्टल पर किसान और उद्योग पराली की गाठों / बेलों का क्रय-विक्रय कर सकते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2020-21 में 24409 किसान पोर्टल पर पंजीकृत हुए थे और इस पोर्टल पर 147 औद्योगिक इकाईयों द्वारा 896963 मीट्रिक टन पराली की आवश्यकता के लिए अपना पंजीकरण करवाया गया था। उपरोक्त स्कीम का उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित कर पराली का उचित निष्पादन करना है। उन्होंने बताया कि पराली की गाठें बनाने वाली स्ट्रा बेलर युनिट भी किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाता है।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक व अन्य औद्योगिक इकाईयों जो पराली की बेलों का उपयोग करती हैं, को कहा है कि वे सभी चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पराली की गाठों / बेलों की आवश्यकता अनुसार मांग हेतु अपना पंजीकरण उपरोक्त पोर्टल पर करवा लें, ताकि समय पर उन्हें पराली उपलब्धता हो सके।

-संवाद ब्यूरो

365 दिन ही मनाएं 'जल दिवस'

समाज में तीज-त्योहारों का अपना महत्व है। धर्म की तरह समाज के बाकी हिस्सों में भी गैर-सामाजिक व राजनीतिक हिस्सों में भी पिछले कुछ वर्षों से हम सब तरह-तरह के दिवस मनाने लगे हैं।

जल दिवस उसी तरह का एक दिवस है। चौमासा वर्षा के स्वागत व सम्मान के लिए जाना जाता है। उसके आने की तारीखें वर्षा लाने वाले नक्षत्रों के हिसाब से ही तय होती हैं। इसी तरह चार महीने के समापन की तिथियां भी बादल समेटने के नक्षत्रों से जोड़कर देखी गई हैं। ऐसे सब आयोजन हमारे समाज की स्मृति में हज़ारों सालों से रचे-बसे हुए हैं, लेकिन विश्व जल दिवस जैसे अनेक नए दिवस हमारे जीवन में नए आए हैं।

जल दिवस पर उत्साह ऐसा होना चाहिए कि वह आने वाले लंबे समय तक हमें पानी की कमी, उसकी सफाई, उसके संग्रह और संग्रह के बाद उसके किफायत के साथ किए जाने वाले उपयोग की बराबर याद दिलाता रहे।

जल दिवस विश्व के स्तर पर शुरू हुआ है और इसे हम पूरे देश में मनाते हैं, इसलिए मोटे तौर पर इस दिन हम सबका इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि हम अपने-अपने इलाकों में थोड़े ही दिनों बाद सिर उठाने वाले जलसंकट को अपने ध्यान में रखें और उसकी मार को कम करने के लिए थोड़ी ईमानदारी के साथ तैयारी करें। पूरे देश में जल से जुड़ी समस्याओं का आभास होने लगा है। देश के एक कोने से चलें, तो कन्याकुमारी में तीन तरफ विशाल सागर है। मीठा पानी बहुत कम है, लेकिन बादलों की और वर्षा की कोई कमी नहीं है, इसलिए वहां के समाज ने वर्षों से वर्षा जल के संचय की अनेक योजनाओं पर काम किया। उन्हें लागू किया और सदियों तक उनका रखरखाव किया। दक्षिण में ही बेंगलूरू जैसे शहर में शायद सबसे अधिक तालाब हुआ करते थे। अब गर्मी के मौसम में शहर को पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है। चेन्नई जैसे शहर में न वर्षा की कमी थी और न वर्षा जल को सम्मान से रोक लेने वाले तालाबों की, आज वहां भी तालाब गायब हो रहे हैं।

अहमदाबाद में शहर के कोने से लेकर बीच तक एक से एक तालाब हुआ करते थे, जो वर्षा जल संचय करके शहर के भू-जल का स्तर ऊंचा रखते थे। आज वहां के नागरिक हाईकोर्ट तक गए हैं, लेकिन अपने तालाबों को बचा नहीं पाए हैं। भोपाल में एक समय जो देश का सबसे बड़ा तालाब माना जाता था, आज वह न सिर्फ सिकुड़कर दसवां हिस्सा रह गया है, वह शहर की पानी की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा है।

हरियाणा के नारनौल जैसे कई ज़िले भी कभी तालाबों के जनपद कहलाते थे , लेकिन आज प्रदेश के अनेक ज़िले भूजल स्तर गिरने के कारण रेड जोन में हैं। हालांकि प्रदेश सरकार अस्तित्व खो चुके लगभग 21 हज़ार तालाबों को पुनर्जिवित करने के लिए सेटेलाइट सर्वे करवाने में जुटी है। इसमें पूरे प्रदेश में 18, 437 तालाब चिन्हित भी किये गए हैं। जबकि प्रदेश में बड़ी संख्या में तालाबों की ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़े हैं। फिलहाल सरकार ने 430 गांवों में 1,492 तालाबों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने में सरकार जुट गई है।

-सुरेंद्र बांसल

जैविक खेती अपनाएं, आमदनी बढ़ाएं

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज ने कहा कि दिनों-दिन जैविक उत्पादों की तरफ आम आदमी का रूझान बढ़ रहा है, लेकिन जैविक खेती की ओर अभी भी कम किसान आगे आ रहे हैं। इसलिए भविष्य में वैज्ञानिक जैविक खेती की सभी फसलों की समग्र सिफारिशें विकसित करें और इसके लिए कम जोत वाले किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाना चाहिए। वे विश्वविद्यालय के दीन दयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र के वैज्ञानिकों से समीक्षा बैठक के दौरान रूबरू हो रहे थे।

जैविक खेती को बढ़ावा

उन्होंने कहा कि जैविक उत्पदों की गुणवत्ता बनाए रखने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार के शोध कार्यों को बढ़ावा दें जो प्रत्येक किसान की पहुंच में हो सके। साथ ही प्रत्येक किसान अपने खेत में उसका प्रयोग करने में समर्थ हो। कुलपति ने कहा कि एचएयू उत्तर भारत का अपने आप में एक अनूठा विश्वविद्यालय है जहां जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इसलिए वैज्ञानिकों का कर्तव्य बनता है कि इस केंद्र के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रेरित व जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में हमारे देश व प्रदेश में जैविक खेती के प्रति किसानों, कृषि वैज्ञानिकों व आम उपभोक्ताओं का रूझान बढ़ा है। जैविक उत्पादों को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ-साथ पौष्टिक, स्वादिष्ट व रसायानों से मुक्त होते हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान करते हुए कहा कि अपने शोध प्रयोगों को इस तरह से आगे बढ़ाएं जिसमें आवश्यक सभी विषयों का समन्वय हो ताकि उपभोक्ताओं तक इसकी गुणवत्ता पहुंच सके। इसके अलावा अनुसंधान पहलुओं को टुकड़ों की एक पूरा पैकेज खोजा जाए जिसमें पैदावार, गुणवत्ता व प्रोसेसिंग शामिल हो। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों को अनुसंधान प्रयोगों में सुधार तथा किसान हितैषी बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए।

फल वाले पौधों के बीच सब्जी व अन्य फसलों का हो अंतकरण

अनुसंधान निदेशक डॉ. एस.के. सहरावत ने जैविक खेती के लिए सूक्ष्म सिंचाई विधि से फर्टीगेशन करने पर ड्रिपर बंद होने की संभावना का समाधान ढूंढने, फल वाले पौधों के बीच सब्जी व अन्य फसलों का अंतकरण व विभिन्न फसलों का पूरे साल का फसल चक्र विकसित करने के लिए अनुसंधानों पर ध्यान देने पर जोर डाला। दीन दयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक डॉ. अनिल कुमार ने केंद्र में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह केंद्र करीब 150 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें बागवानी, सब्जियों के साथ-साथ अन्य फसलों को भी जैविक रूप से तैयार किया जाता है। यह प्रदेश के किसानों को ऑर्गेनिक फल और सब्जियों को उगाने के प्रति प्रेरित करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

दरअसल, किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से ही इस केंद्र की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। वर्तमान में एचएयू में विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों व अनाजों को बिना रसायनिक पदार्थों का प्रयोग किए खेती की जा रही है। जैविक खेती से किसान उत्पादन में वृद्धि व आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे मिट्टी के जैविक गुण और उपजाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। किसान जैविक खाद और जैविक इंसेक्टिसाइट का उपयोग करके एक बेहतर फसल ले सकते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता और खेत में सूक्ष्म जीव और वनस्पतियों को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होते हैं व मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। इस बैठक में आगामी वर्ष 2021-22 की रूपरेखा भी तैयार की गई।

- संवाद ब्यूरो

आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों, हिंदी आंदोलन में शामिल रहे लोगों एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों एवं उनके आश्रितों तथा मान्यताप्राप्त पत्रकारों को दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के संपत्ति कर पर 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के लिए 30 सितंबर, 2021 तक 10 प्रतिशत की छूट भी दी गई है।

सक्षम हरियाणा के सकारात्मक परिणाम

मनोज प्रभाकर

स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से चलाए जा रहे राज्यव्यापी शिक्षा बदलाव कार्यक्रम 'सक्षम हरियाणा' के सकारात्मक परिणाम नजर आने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में करीब नब्बे प्रतिशत विद्यार्थी सक्षम या ग्रेड लेवल सक्षम हो गए हैं। कई दौर के आकलन के बाद प्रदेश के कुल 107 खंड सक्षम हो गए हैं, जबकि प्रदेश में 14 जिले शत-प्रतिशत सक्षम हो गए हैं।

अध्ययन अभिवृद्धि कार्यक्रम के माध्यम से रेमेडियल शिक्षा, प्रदेश में शैक्षणिक समीक्षा तथा निगरानी तंत्र के मजबूतीकरण और शिक्षा विभाग की प्रौद्योगिकी प्रणालियों (प्रबंधन सूचना प्रणाली शैक्षणिक निगरानी प्रणाली) में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है। केन्द्रीकृत परीक्षाएं आयोजित करके डाटा संग्रहण और डाटा विश्लेषण में सुधार लाकर तथा नकल में कमी करके आकलन सुधार किए जा रहे हैं।

इन पहलों के माध्यम से राज्य का लक्ष्य 'सक्षम' बनना अर्थात प्रदेश में 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ग्रेड लेवल दक्षता हासिल करना है। ग्रेड लेवल दक्षता से अभिप्राय है कि किसी विशेष ग्रेड का विद्यार्थी उस ग्रेड के लिए परिभाषित सभी दक्षताओं या कौशलों से परिचित हो। अर्थात यदि ग्रेड 7 का कोई विद्यार्थी ग्रेड 7 में पढ़ाई जाने वाली दक्षताओं से परिचित है तो वह ग्रेड लेवल सक्षम है। किसी भी खंड को सक्षम होने के लिए इसके 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों को ग्रेड लेवल सक्षम होना चाहिए। जिले को सक्षम होने के लिए इसके सभी खंडों का 'सक्षम' होना आवश्यक है। हरियाणा को सक्षम होने के लिए इसके सभी जिलों को सक्षम होने की आवश्कता है।

ग्रेड 3, 5 और 7 के विद्यार्थियों का सेंपल आधार पर भाषा (हिन्दी) और गणित में मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे स्कूल जो कि ग्रामीण, शहरी, लड़कों, लड़कियों, प्राथमिक और माध्यमिक का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हों, के चयन के लिए वैज्ञानिक सेंपलिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। इन स्कूलों में थर्ड पार्टी मूल्यांकन करवाया जाता है। थर्ड पार्टी मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि वह खंड वास्तव में 'सक्षम' बन गया है या नहीं।

प्रदेश के जो 14 जिले पूर्ण रूप से सक्षम हुए हैं उनमें झज्जर, चरखीदादरी, कैथल, भिवानी, पंचकूला, महेन्द्रगढ़, करनाल, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, सिरसा, रेवाड़ी, हिसार और जींद शामिल हैं। सक्षम घोषित किए गए 13 नए खंडों में अग्रोहा, बाबैन, बरवाला, बहल, जगाधरी, कलानौर, मुस्तफाबाद, पिंजौर, रायपुररानी, रतिया, सीवान और सिवानी शामिल हैं। इसीप्रकार, जो आठ खंड सक्षम बनने वाले हैं उनमें बराड़ा, बल्लभगढ़, फिरोजपुर झिरका, लाडवा, नगीना, पुन्हाना, रोहतक और टोहाना शामिल हैं। इसके अलावा, चार गैर सक्षम खंडों में अम्बाला-1 (शहर), अम्बाला-2 (छावनी), छछरौली और हथीन शामिल हैं।

जो खंड हिन्दी और गणित में 'सक्षम' या ग्रेड लेवल सक्षम बने हैं, उन्हें 'सक्षम प्लस' का दर्जा देने के लिए अंग्रेजी में मूल्यांकन किया गया। फरवरी, 2019 में पांच खंडों का परीक्षण किया गया जिनमें से एक को 'सक्षम प्लस' का दर्जा मिला। मई, 2019 में 26 और खंडों का परीक्षण किया गया तथा चार खंडों को 'सक्षम प्लस' का दर्जा दिया गया।

खंडों को सक्षम और सक्षम प्लस बनाने के लिए जिले के समन्वय से खंड में कई सुधार ''यान्वित किए गए। विस्तृत जिला स्तरीय के साथ-साथ सूक्ष्म खंड स्तरीय योजना और क्रियान्वयन किया गया।

दक्षता आधारित अध्यापन, एलईपी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और निगरानी दौरे किए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमजोर विद्यार्थियों, दक्षताओं और स्कूलों को लक्षित सभी कदम सुनिश्चित किए गए हैं, खंड और स्कूल स्तर पर नियमित तौर पर पूर्व मूल्यांकन संचालित किए गए और डाटा मूल्यांकन किया गया।

ओलंपिक में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोक्यो ओलंपिक के भव्य उदघाटन समारोह को देखते हुए इसमें भाग लेने वाले भारतीय दल, विशेषकर हरियाणा के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। टोक्यो ओलंपिक-2020 में भाग लेने वाले 126 खिलाड़ियों के भारतीय दल में हरियाणा से 31 खिलाड़ी (25 प्रतिशत) शामिल हैं।

सीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह एवं विभाग के निदेशक श्री पंकज नैन और प्रचार प्रकोष्ठ के ओएसडी श्री गजेंद्र फोगाट भी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार, बेहतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की राशि दी गई। इसके अलावा भी इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए, जिनके तहत राज्य के प्रतिनिधि इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के परिवारों से मिले और उनके सामने आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी ली।

उत्कृष्ट शिक्षा है विकास का मूल आधार

इस तथ्य से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत देश प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में सिरमौर रहा है। इतना ही नहीं विश्व की अन्य सभ्यता एवं संस्कृतियों के क्षेत्र में भी हमारे देश ने नेतृत्व किया है। इसके प्रमाण न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व के अन्य भागों में भी तलाशे जा सकते हैं।

पंद्रहवीं सदी के आरम्भ तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 29 प्रतिशत थी। जो आज घटकर 1.71 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है। ऐसा क्यों था? इसका सीधा सा जवाब शिक्षा तंत्र रहा जो प्राचीन काल में बहुत व्यावहारिक और सुस्थापित था। गुरुकुल सबसे छोटी इकाई होती थी जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार मानते हुए विधार्थी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता था।

इसके बाद यह व्यवस्था ऋषिकुल, महाऋषिकुल एवं राजऋषिकुल तक विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचती थी। सम्पूर्ण शिक्षा के लिए अलग-अलग विभाग एवं प्रयोगशालाओं की व्यवस्था थी। ज्ञान से विज्ञान, शास्त्र से अस्त्र शस्त्र, जन्म से निर्वाण, ग्रहस्थ से सन्यास, परमाणु से ब्रहमांड के जीवन चक्र की शिक्षा पर पठन पाठन होता था। उसमें देश-काल, समय-स्थान लिंग आदि का कोई भेद न था।

चुनौतियों से पार पाने के लिए समयबद्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रयोग किया है और स्थानीय भाषा के साथ-साथ विदेशी भाषाओं के माध्यम से भी परहेज़ नहीं किया। आजादी के बाद भारतीय शिक्षा नीति में रोजगार उसका उद्देश्य रहा। गूढ़ज्ञान और शोध का स्थान डिग्री और नौकरी हासिल करने में परिवर्तित होता चला गया।

वर्तमान केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसमें नई चुनौतियों से पार पाने के लिए शोध और विज्ञान पर फोकस किया गया है। शिक्षा को अधिक ज्ञानोन्मुख और तकनीक से संबद्ध करना, स्थानीय भाषा के साथ-साथ विदेशी भाषाओं को तरजीह देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण नीति आदि अनेक ऐसी पहलें की गई हैं जिनका आने वाले समय में सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा पर नये सिरे से विचार कर 3+2+3 व्यवस्था अपनाई गई है।

नई शिक्षा नीति लागू करने में हरियाणा प्रदेश अग्रणी राज्य हो गया है। समय तेजी से बदल रहा है। देश और अधिक इंतज़ार नहीं कर सकता। वैश्विक चुनौतियां जितनी आज हैं पहले नहीं थी। पहली दोनों औद्योगिक क्रान्तियां भारत चूक गया था अब देश इतना जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है कि 135 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की अनदेखी की जाए। यह सब समकालीन शिक्षा नीति से संभव नहीं है।

युवाओं को स्कूली स्तर पर ही एक सुदृढ़ नींव प्रदान करने के लिए 113 नए 'संस्कृति मॉडल स्कूल' खोले गए हैं, ताकि जीवन मूल्यों व मानवीय सिद्धांतों पर केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। मॉडल संस्कृति स्कूलों की कुल संख्या 136 हो गई है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जा रही हैं और 'हरियाणा शिक्षक परीक्षा योग्यता' को भी अब आजीवन स्वरूप दिया जा रहा है।

अभिभावकों की इच्छानुरूप इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों में सभी आधुनिक सुविधाएं मयस्सर कराई गई हैं। स्मार्ट क्लास व दृश्य-श्रव्य सहयोग सामग्री पर विशेष ध्यान दिया गया है।

दीवारों पर अंकित छवियों से पठन-पाठन का वातावरण बनता प्रतीत होता है। न केवल प्राथमिक शिक्षा पर नये सिरे से ध्यान दिया गया है बल्कि माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय शिक्षा पर भी समुचित बल दिया गया है, स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के अलावा सुसज्जित प्रयोगशालाएं, दक्ष प्राध्यापक, कंप्यूटर, आई टी, सिक्योरिटी, भाषा प्रयोगशाला आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। खास बात यह है कि उपरोक्त सुविधाओं के कारण इन स्कूलों में गुणवत्ता के साथ साथ प्रयोगधर्मी वातावरण विकसित हो रहा है।

नई शिक्षा नीति पर पूरी ईमानदारी एवं सामर्थ्य से कार्य हुआ तो देश पुनः विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में होगा। ऐसा मेरा मानना है।

गुलाब सिंह,
प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान
राजकीय माडल
संस्कृति स्कूल गन्नौर,
सोनीपत

प्रदेश के दिव्यांगजन अब राज्य पुर्नवास, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान रोहतक में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। पंजीकरण शुल्क, मासिक शुल्क तथा हॉस्टल फीस माफ़ कर दी है।

हिसार के कुलपति प्रो. बी.आर काम्बोज ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के लिए एक करोड़ तीन लाख दो हजार तीन सौ इक्कीस रुपए का चैक भेंट किया। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से फंड के लिए यह दान दिया गया है।

करनाल-यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी

'करनाल-यमुनानगर' नई रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। इस संबंध में सितंबर,2019 में प्रेषित मसौदा रिपोर्ट में रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी सुझावों को शामिल करने के उपरांत हरियाणा सरकार ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी।

हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम ने 883.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस डीपीआर को अंतिम रूप दिया है । यह परियोजना लगभग चार वर्ष की अवधि में क्रियान्वित होगी।

निगम से मिली जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित करनाल-यमुनानगर नई रेल लाइन दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन पर मौजूदा करनाल रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और अंबाला-सहारनपुर रेलवे लाइन पर मौजूदा जगाधरी-वर्कशॉप रेलवे स्टेशन से जुड़ेगी।

करनाल, पानीपत और मध्य हरियाणा के अन्य हिस्सों को सीधा संपर्क प्रदान करते हुए यह नई लाइन पूर्वी डीएफसी के लिए एक फीडर मार्ग के रूप में कार्य करेगी, जिसमें कलानौर स्टेशन (यमुनानगर के साथ) पर रेलवे के साथ इंटरचेंज पॉइंट होगा।

सड़क मार्ग से कम दूरी तय होगी

अंबाला छावनी के रास्ते करनाल से यमुनानगर तक मौजूदा रेल मार्ग से दूरी 121 किलोमीटर है। करनाल और यमुनानगर के बीच सड़क मार्ग से दूरी 67 किलोमीटर है। इस प्रकार 64.6 किलोमीटर लम्बी यह प्रस्तावित नई रेलवे लाइन, इन दोनों शहरों के बीच सबसे छोटा लिंक प्रदान करेगी और यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए यात्रा के समय को बहुत कम कर देगी।

परियोजना से फायदे

परियोजना से प्रमुख लाभों में इंद्री, लाडवा और रादौर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उपज, प्लाईवुड एवं लकड़ी, औद्योगिक उत्पादों, धातु उद्योग, उर्वरकों आदि के लिए बाजार तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होना शामिल है। इसके अलावा, यह परियोजना हरियाणा के दक्षिणी एवं पश्चिमी हिस्सों को पवित्र शहर हरिद्वार से सीधे जोड़ेगी।

-संवाद ब्यूरो

सीएम ने आवास पर सुनी जन समस्याएं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में जनता दरबार लगाकर प्रतिनिधि मण्डलों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही उनके निवारण हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एक प्रतिनिधि मंडल ने विभाग में नियमित और स्थाई भर्ती को लेकर अपनी मांग रखी जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने तुरंत जरूरी दिशा-निर्देश दिये। जिला हिसार की नारनौंद अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग रखी, जिसमें अधिकारियों से 50 प्रतिशत हुए गेहूं के नुकसान की भरपाई के बारे में आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मामले में कड़ा संज्ञान लिया और खाद्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को तुरंत प्रभाव से संबंधित 9 अधिकारियों से रिकवरी करने के आदेश दिए और कहा कि जो सरकारी नुकसान हुआ है उसकी आधी भरपाई दोषी अधिकारियों से की जाये।

करनाल के अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अशोक धींगड़ा की अगुवाई में मुख्यमंत्री के समक्ष एस्टेट एरिया से संबंधित कई समस्याएं रखी गई जिस पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक को दिशा निर्देश दिए।

हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी ने विभाग के संबंध में कई नीतिगत फैसलों की मांग की गई जिस पर मुख्यमंत्री ने विभाग को सात दिन के अंदर अपनी लिखित टिप्पणी देने को कहा।

बहादुरगढ़ फुटवियर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने किसान आंदोलन के कारण हो रही समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी मनोज यादव को इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने के आदेश दिए। बहादुरगढ़ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट की यूनियन ने सीवर और सडकों के बनने की धीमी गति बारे अवगत करवाया जिस पर उन्होंने एचएसआईआईडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनुराग अग्रवाल को कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने के आदेश दिए।

कई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने फायर एनओसी मिलने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया जिस पर मुख्यमंत्री ने अर्बन लोकल बॉडीस डिपार्टमैंट के अधिकारियों को तुरंत जांच के आदेश दिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।

इस दौरान आयुर्वेदिक मेडिकल अफसरों के प्रतिनिधि मंडल ने मांगे रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में सीसीएच टेस्ट की अनिवार्यता एनएचएम के कर्मियों में समाप्त करने के आदेश दिए और जो मौजूदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें डिपार्टमैंट को 15000 रूपये प्रतिमाह मानदेय देकर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से टेस्ट देने में मदद करने को कहा और किसी भी कर्मचारी को सीसीएच टेस्ट के चलते नौकरी से नहीं निकाला जाए।

ग्राम दर्शन पोर्टल पर दे सकेंगे सुझाव व शिकायत

प्रदेश के लोगों की विकास कार्यों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल तैयार किया गया है। यह एक सुगम तरीका रहेगा जिससे कहीं पर भी बैठकर अपनी मांग/सुझाव और शिकायतों को दर्ज किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इससे संबंधित ऑनलाइन पोर्टल 'ग्राम दर्शन' का लोकार्पण किया। ग्रामीणों द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग की पांच कामों की प्राथमिकताएं तय करें ताकि ग्रामीणों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों और सुझावों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके।

सीएम विंडो से लिंक किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर की जाने वाली शिकायतों को सीएम विंडो के साथ लिंक किया जाएगा ताकि शिकायतों का दोहराव न हो। मुख्यमंत्री ने ग्राम दर्शन पोर्टल का लिंक 'जन सहायक' एप्प के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए।

गांव की शिकायत दर्ज हो सकेगी

ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थाई निवास के गांव (जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो) के सम्बंध में शिकायत/सुझाव और मांग दर्ज कर सकेगा।

जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेगी

ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डेशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें सम्बन्धित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।

एसएमएस से मिलेगी स्टेटस रिपोर्ट

पोर्टल पर सुझाव/शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जेनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव/शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट सूचना एसएमएस के मध्यम से मिलती रहेगी।

कम से कम 50 अक्षर में कर सकेंगे शिकायत दर्ज

आवेदक को ग्राम दर्शन पोर्टल पर शिकायत/सुझाव दर्ज करते समय कम से कम 50 अक्षरों में अपनी बात कहनी होगी। इसके अलावा आवेदक फोटो अपलोड करके अपनी समस्या/सुझाव सरकार को दे सकेंगे। केवल वही आवेदक इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकेगा जिसका परिवार पहचान पत्र होगा।

-संवाद ब्यूरो

साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों के लिए मांगी प्रविष्टियां

हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए अकादमी की आठ विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा अधिवासी लेखकों और साहित्यिक संस्थाओं से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं।

इन योजनाओं में साहित्यकार सम्मान योजना, युवा लेखक सम्मान योजना, श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना (हिन्दी, हरियाणावी व अंग्रेजी), युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना (हिन्दी, हरियाणावी), युवा हिन्दी कहानी प्रतियोगिता, पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रोत्साहन योजना (हिन्दी व हरियाणावी), अभावग्रस्त लेखकों को आर्थिक सहायता अनुदान योजना और साहित्यिक लघु पत्रिकाओं को अनुदान योजना शामिल है।

विस्तृत जानकारी के लिए सूचना पत्र अकादमी कार्यालय से दस्ती या डाक द्वारा निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अकादमी की वेबसाइट haryanasahityaakademi.in से भी विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित सूचना पत्र, नियमावली और आवेदन के लिए प्रपत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। उक्त योजनाओं के तहत प्रविष्ठियां जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2021 है। अकादमी की ओर से यूट्यूब चैनल भी प्रारंभ किया गया है।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में नए अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न स्किल कोर्सिज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 15 सितंबर 2021 तक प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों नामतः पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण जोकि सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।

चौंगरदे तैं बाग हर्‌या, घनघोर घटा सामण की

किसी भी देश - प्रदेश के मेले और त्योहार वहां की संस्कृति का अभिन्न अंग होते हैं। मेले और त्योहारों में देश की आत्मा बोलती है और प्रजा की हार्दिक भावनाएं मुखरित होती हैं। हरियाणवी लोकजीवन में भी 'तीज' ऐसा ही त्योहार माना जाता है। इसीलिए लोक में यह उक्ति प्रचलित है कि 'आई तीज, बिखेरगी बीज' यानी लोक में तीज से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। तीज बच्चों, बालिकाओं नव विवाहिताओं के लिए विशेष आकर्षण का त्योहार है, जबकि पुरुषों के लिए यह मस्ती की अभिव्यक्ति का परिचायक होता है। सामान्य रूप से देहात में एक-दूसरे से जब हाल-चाल पूछते हैं तो भी एक-दूसरे की अभिव्यक्ति 'तीजां बरगे कट रहे हैं' से होती है। इससे पता चलता है कि सावन और तीज की मस्ती आंचलिक जीवन पर कैसे सिर चढ़ कर बोलती है।

बीते वर्षों में सामाजिक जीवन में आए परिवर्तनों का प्रभाव तीज पर भी पड़ा है। अब तीज के अवसर पर महिलाओं के झुंड गीत गाते हुए दिखाई नहीं देते। और न ही देहात में देवर भाभियों को पाटड़ों पर बैठाकर झूलाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं ग्रामीण महिलाएं सज-धज कर झूलने के लिए जिन समूहों में जाती थी वो समूह भी आज फीके हो चले हैं। भगदड़ में पड़ी सभ्यता के दौर ने पारम्परिक त्यौहारों, रस्मों, रिवाजों, लोकगीतों का रंग फीका कर दिया है। सावन के गीत-मल्हार सुनने को कान तरस गए हैं। कंक्रीट के जंगल बसाने के लिए वे ऊंचे पेड़ बलिदान कर दिए गए जिन पर तीजों के झूले पड़ा करते थे। इसीलिए दादा लखमी चन्द की रागनी की यह पंक्तियां भी अब तो अप्रासंगिक हो चली हैं, जिनमें उन्होंने सामण के झूलों का बखान कुछ इस तरह से किया है:

चौंगरदे तै बाग हर्‌या, घनघोर घटा सामण की,
छोरी गावैं गीत सुरीले, झूल घली कामण की।

तीज हरियाणवी लोकजीवन में विशेष महत्ता रखत है। तन झुलसा देने वाली गर्मी के बाद जब सावन-भादों आते हैं, तो रिमझिम फुहारों से तन - मन को शीतलता प्रदान होती है, भीषण गर्मी से तपती धरती राहत की सांस लेकर हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। तीज समस्त उत्तर भारत में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। चूंकि सावन में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है, इसलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। तीज के झूले झूलने के बाद शाम को घर आकर सरसों के तेल के गुलगुले, मट्ठी , शक्करपारे आदि बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। तेल से उठती महक हर किसी की भूख बढ़ा देती है। भादों में सरसों का तेल खाने पर जोर दिया जाता है। माना जाता है कि यह खान पान बरसाती दिनों में त्वचा रोग से बचाता है।

हरियाणा में सावन माह शुरू होते ही नवविवाहितों के लिए 'सिंधारा' एवं 'कोथली' भेजने का काम शुरू हो जाता है। नई नवेली पहली तीज पर अपने पीहर में रहकर खुश होती है, कहते हैं, पार्वती ने भी पहली तीज अपने पिता पर्वतराज के घर मनाई थी। अब भी तीज पर भाई अपनी बहन की ससुराल उपहार लेकर जाता है, जिसे कोथली कहते हैं। कोथली में वस्त्र आदि व मीठे पकवान होते हैं। कोथली ले जाने के अवसर पर महिलाएं यह गीत गाती हैं:

मिट्ठी तो कर दे री मां कोथली,
साम्मण री आया गूंजता।
जाऊंगा री बाहण के देश,
साम्मण री आया मां गूंजता।

हरियाणा के लोक जीवन में सिंधारे में रेशम की डोरी तथा पाटड़ी के साथ सिंधारे में घेवर-फिरनी जैसी मिठाई ज़रूर भेजी जाती है। कोथली के महत्त्व का ब्यौरा इस गीत में भी मिल रहा है:

करदे री मां कोथली,
जांगा बाहण के देश।
ऊंचै सी चढ़ के देख ल्यूं,
कितसी री आवै माई जाया वीर,
जांगा बाहण के देश।
किसकी रे लाया कोथली
किसके रे झूठे सुहाल,
जांगा बाहण के देश।
तेरी ल्याया बेबे कोथली,
मौसी के झूठे सुहाल,
जांगा बाहण के देश।
किसकी रे बीरा चूंदड़ी
किसका रे दक्खनि चीर,
जांगा बाहण के देश।
तेरी हो बेबे चूंदड़ी
मौसी का दक्खनि चीर
जांगा बाहण के देश।
पाड़ू रे तोड़ू चूंदड़ी
ओढ़ू रे दक्क खनि चीर,
जांगा बाहण के देश।

कोथली बहन और भाई के प्यार का प्रतीक है। देहात में नवविवाहित बहू-बेटियों की टोलियां अब कहीं झूलती नज़र नहीं आतीं । अब वो तीज-त्योहार मानो औपचारिकता निभाने को रह गए हैं। सदियों सदियों से ये तीज त्यौहार ही हैं जो हमें जोड़े रखते रहे हैं। हमारे जीवन में उत्साह ,उल्लास, प्रसन्नता भाईचारे को बढ़ाने में सहायक रहे हैं। आइए संकल्प लें कि हम अपने तीज त्योहारों को नहीं बिसराएंगे, उन्हें पूरे उल्लास एवं उमंग से मनाएंगे ताकि हमारा परिवार व समाज सदैव प्रेम एवं सौहार्द की भावना से ओतप्रोत रहे।

-संवाद ब्यूरो

सुण छबीले-बोल रंगीले

-रंगीले भाई राम राम, आज तो कस्सी ठार्‌या सै। के कमावैगा?

-भाई छबीले, खेत मं जा सूं, पाणी का ओसरा सै। थोड़ा ईख बो राख्या सै, उसके पत्ते चोटी मं तैं पीले पड़ण लाग गे। पाणी मिल ज्यागा तो जी-सा आज्यागा।

-देखिए ईख मं कदे कोई रोग लागर्‌या हो। कृषि विभाग में फोन करकै पूछताछ कर ले।

-पहल्यां पाणी दे ल्यूं फेर दफ्तर में जाकै आऊंगा। और सुणा तेरा के हाल सै?

-आज्या होक्का पी ले। क्यूं सारी हाणा चक्करां में पड़्या रहा करै। ईब तो छोरा भी नौकरी लागग्या। गात नै टिका बी लिया कर।

-भाई इतणै हाड-गोडे चालैं सैं इतणै चला लें। जै काम करणा बंद कर दिया तो फेर ये कतई जाम होज्यांगे। पर छबीले छोरा तो तेरा भी नौकरी लागर्‌या सै। तूं क्यूं दिहाड़ी मजूरी पै जाया करै?

-रंगीले तेरे और मेरे छोरे में फर्क सै। तेरा छोरा तो लाग्या सै बिना कुछ लिए-दिए, और मेरा छोरा आठ साल पहल्यां लाग्या था ले देकै। कर्जा ठा कै सरकारी नौकरी लगवाया था। वो कर्जा ईब ताहीं लटकै सै। जिब्र ताहीं ना उतर लेता, दिहाड़ी मजूरी तो करणीए पड़ैगी। ना करैंगे तो किस नै बतावैंगे।

-बात तो ठीक कहै सै छबीले, कर्जे में माणस की उम्र बी घटज्या सै। चाल कोए बात ना। ईब तो घणी गई, थोड़ी रही। क्यों चिंता करर्‌या सै। बालक लायक हो ना तो कर्जा-वर्जा तावला ए उतर जाया करै। भाई छबीले, म्हारै तो जी-सा आग्या। नौकरी लागण में एक पिस्सा नहीं लाग्या। जै हो इस चाचा सरकार की।

-रंगीले एक बात तो देखी। पहल्यां नौकरी लागण खातर निरे माणस हाथ में पर्ची लेकै लीडरां के आगै पाछै हांड्या करते। चाहे पार्टी का कार्यकर्ता भी था, उसके घरां भी मिलण आळां की लाइन लागी रहा करती। लेण-देण भी हो था और आड़-परछाड़ की रिश्तेदारी भी काढी जावै थी। फेर बी कोई गारंटी ना थी, काम हो, ना हो। और ईब किसे नेता के आगे-पाछै भीड़ ला लागती। पार्टी वर्करां की बात-ए दूर सै। बाळक भी तकरीबन सबके लागैं सैं।

-भाई, सीधी सी बात सै। जो बाळक पढ़ैगा वो नौकरी लागैगा। ना पढैगा तो म्हारे की तरियां न्यूए डांगरा के आगै-पाछै हांडैगा।

-और जिसका पढण नै जी ना करता हो वो खेलां में भाग ले ले। खेलण आले बालक भी नौकरी आल्यां तै कम ना सैं। सारे किस्से छोड़, जै कोई काम बसका ना सै तो 'पकड़ कस्सी और चाल खेत में'।

-देख छबीले, एक बात कहणी पड़ैगी। इस सरकार ने किसानां ताहीं सहारा भतेरा ए दे राख्या सै। बीज, खाद, दवाई, कृषि के उपकरण सब क्याहें में सबसिडी की व्यवस्था कर राखी सै। खेत में फसल खराब होज्या तै बीमे के रपइये मिलज्यां। फसल ठीक होज्या तो पूरे दाम मिलज्यां। मंडी में बेचो चाहे बाहर मार्केट में बेचो। मर्जी आपणी। जड़ै दो रपइये ठीक मिलते हों उड़ै बेचै।

- हां भाई, कई सारे उपकरण तैं इसे सैं उनपै अस्सी परसेंट ताहीं सबसिडी दी जाण लागरी सै। बिजली पाणी की कोई कमी ना। और के राम लूटैंगे।

आच्छा चालूं सूं। जै रामजी की।

-मनोज प्रभाकर

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com